By: Dr. Shailesh Kr
dept. of economics
Raja singh college
Siwan

भारत में रोजगार परिदृश्य

Employment perspective in India

भारत में 100 लाख रोजगार प्रति वर्ष कायम करने संबंधी विशेष ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर, दसवीं योजना ने अनुमान लगाया कि 2001-02 में बेरोजगारों की संख्या लगभग 348.5 लाख थी। इसमें दसवीं योजना के अनुसार श्रम शक्ति में वृद्धि के रूप में 352.9 लाख व्यक्तियों का अनुमान है। इस प्रकार दसवीं योजना के अनुसार 701.4 लाख कुल रोजगारों (348.5 + 352.9 = 701.4) की आवश्यकता होगी।

सकल देशीय उत्पाद की 8 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर दसवीं योजना के दौरान 296.7 लाख रोजगार सामान्य रूप में ही कायम होंगे। जाहिर है कि अतिरिक्त श्रम शक्ति में वृद्धि (352.9 लाख) के लिए भी पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध कराये जा सकेंगे, और इसके लिए 56.2 लाख रोजगार अवसरों की जरूरत होगी। इसके परिणाम स्वरूप, कुल बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर 404.7 लाख हो जाएगी।

इसे हम विस्तृत तरीके से जानने के लिए निम्न तालिका का अध्ययन करेंगे।

दसवीं योजना के दौरान प्रोग्राम जनित अतिरिक्त रोजगार

	रोजगार अवसर (लाख में)
कृषि तथा संबद्ध क्रियाएं	35.5
कृषि वानिकी द्वारा देश को हरा-भरा बनाना	35.0
बायो मास पावर जनन के लिए ऊर्जा बागान	20.1
ग्राम क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्योग	70.6
शिक्षा एवं साक्षरता	17.0
सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी द्वारा रोजगार	7.0
स्वास्थ्य, परिवार और बाल कल्याण सेवाएं	8.0
कुल	193.02

अतः इसका उत्तर ऐसी विकास रणनीति development strategy में निहित है, जिसे श्रम प्रधान उत्पादन के पक्ष में तुलनात्मक लाभ प्राप्त हो।

P.T.O.

Scanned by CamScanner

इसके लिए विशेष ग्रुप ने कुछ ऐसे श्रम प्रधान क्षेत्रों की सिफारिश की है जिनमें नीति संबंधी हस्तक्षेप की जरूरत है। ये क्षेत्र हैं कृषि रवाद्य परिसाधन, खाग फार्म भिन्न क्रियाऐं जिनमें खेती और खाग उद्योग शामिल हैं। लघु तथा मध्यम उद्यम और सेवा क्षेत्र जिनमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सूचना टेक्नोलॉजी और संचार सम्मिलित है। इन प्रोग्रामों आधारित नीति संबंधी हस्तक्षेपों में 193.2 लाख रोजगार कायम किए जा सकेंगे।

अतः कुल रोजगार जनन 490 लाख होगा जिनमें 8 प्रतिशत वृद्धि दर के आधार पर 296.7 लाख और प्रोग्राम जनित रोजगार द्वारा 193.2 लाख रोजगार कायम किए जायेंगे। इस प्रकार बेरोजगारी की दर जो 2001-02 में 9.21 प्रतिशत थी कम होकर 2006-07 में 5.11 हो गई।

(लाखों में)

	2001-02	2006-07	अन्तर
1. श्रम शक्ति —	3,782.1	4,135.0	352.9
2. रोजगार —	3,433.6	3,923.5	488.9
3. बेरोजगारों की संख्या	348.5	211.5	(-)137.0
4. बेरोजगारी प्रतिशत —	9.21	5.11	

स्रोत योजना आयोग, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)

दसवीं योजना की विफलता और उपलब्धियाँ achievements and failures of the tenth plan)

दसवीं योजना ने 31 मार्च 2007 को पाँच वर्ष पुरा किया चाहे योजना की उपलब्धियों के बारे में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है परन्तु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इसकी उपलब्धियों को समझना होगा। इससे हमें योजना का एक सामान्य सर्वेक्षण प्राप्त होगा।

नीचे दर्शाये गये तालिका में योजना के समष्टि संकेतकों से बोध प्राप्त होता है।

P.T.O.

समष्टि आर्थिक संकेतक

	नवीं योजना 97,98 से 2001-02	दसवीं योजना 2002 से 6-07
1. सकल देशीय उत्पाद जिसमें		
कृषि	5.5	7.6
उद्योग	2.0	2.1
सेवाएँ	4.6	
	8.1	8.9
2. सकल देशीय बचत	23.1	9.3
3. सकल देशीय निवेश	23.8	30.8
4. चालू खाते पर अधिशेष	-0.7	32.0
5. विदेशी मुद्रा रिजर्व		1.3
(अरब, यू०एस० डॉलर)	54.2	165.3
6. स्फीति की दर (थोक कीमत सूचकांक के आधार पर)	4.9	5.1

स्रोत 11वीं पंचवर्षीय योजना 07-12

दसवीं योजना की सराहनीय उपलब्धियाँ

(a) पहली 10वीं योजना 8 प्रतिशत जी०डी०पी० वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायी है परन्तु इसमें नौवीं योजना के दौरान सकल देशीय उत्पाद की 5.5 प्रतिशत वृद्धि दर के विरुद्ध दसवीं योजना अर्थव्यवस्था को और ऊँचा उठाकर इसकी वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत के स्तर पर ले गयी। यह बात बड़ी उत्साहवर्धक है कि योजना के अन्तिम वर्ष में जी०डी०पी० की वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुँच गयी। यह अभिनन्दनीय है।

(b) सकल देशीय बचत (gross domestic saving) बाजार कीमतों पर जी०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में दसवीं योजना में 28.2 प्रतिशत थी जबकि यह इसके विरुद्ध नौवीं योजना में 23.1 प्रतिशत थी। यह भी एक सकारात्मक स्थिति है क्योंकि इसका अभिप्राय यह है कि अर्थव्यवस्था अब बचत के उच्च स्तर तक बढ़ रही है, जो कि 8-9 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। 2005-06 में सकल देशीय बचत बढ़कर 32.4 प्रतिशत हो गयी है। यह वास्तव: गर्व की बात है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की निवेश को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए क्षमता बढ़ गयी है। 2005-06 में सकल देशीय

P.T.O.

Scanned by CamScanner

(5) निवेश के बढ़कर 33.8 प्रतिशत हो गई। यह एक रेकार्ड उपलब्धि है।

(3) अर्थव्यवस्था अपने वर्धमान पूँजी उत्पाद अनुपात (incremental capital output ratio (icor) को जो नौवीं योजना में 4.3 था, दसवीं योजना के दौरान 4.2 पर पायी है। नवीं योजना में पूँजी-निर्माण के प्रत्याशित उच्च स्तर के साथ, यह योजना के अन्त तक जी.डी.पी. में औसत 9 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी।

(4) और विदेशी मुद्रा रिजर्व फरवरी 2007 में 185 अरब यू०एस० डालर के स्तर पर पहुँच गए हैं। यह भी अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत हैं।

(6) विदेशी मुद्रा अन्तर्प्रवाह 2005-06 में 20.2 अरब डॉलर हो गये - 7.7 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (direct foreign investment) के रूप में और 12.5 अरब डॉलर पोर्टफोलियो निवेश के रूप में। चूंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को उन्नत करता है, इसका भाग कुल विदेशी निवेश अन्तर्प्रवाह में केवल 35.6 प्रतिशत है। इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

विफलताएं

(1) योजना आकार में कटौती

दसवीं योजना में 2001-02 की कीमतों पर आयोजित परिव्यय 1525639 करोड़ रुपये तय किया गया परन्तु चालू 2006-07 की कीमतों पर कुल व्यय 1618460 करोड़ रुपये होने की प्रत्याशा है। यदि हम इन आँकड़ों को 2001-02 की कीमतों पर डावस्फ्लेट करें तो यह कटौती कहीं अधिक होगी, क्योंकि दसवीं योजना में औसत वार्षिक स्फीति 5.1 प्रतिशत थी।

(2) लक्षित स्तर तक गरीबी को कम करने में विफलताएं

रोजगार की स्थिति का एक और निराशाजनक पहलू यह है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि 1994-2004 में

P.T.O

Scanned by CamScanner

में नकारात्मक थी। चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र अतिरिक्त श्रमिकों के भार को कम कर रहा था, यह आशा की जाती थी कि निजी क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि दर बढ़ जायेगी परन्तु निजी क्षेत्र में जहाँ 1983-94 तक रोजगार की औसत वार्षिक वृद्धि दर 0.44 प्रतिशत थी यह बहुत मन्द गति से बढ़कर 1994-2004 के दौरान 0.61 प्रतिशत हो गयी,

(3) कृषि क्षेत्र में निराशाजनक निष्पादन

अर्थशास्त्रियों का मत है कि व्यापार शर्तों में किमतों में वृद्धि ने कृषि के संभरण सिमावंधनों को प्रोत्साहन किया है। इस उद्देश्य के लिए सिंचाई और वाटरशैड प्रबंध में निवेश को बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा लगता है कि सरकार जागी है और कृषि में निवेश, विशेषकर सिंचाई और वाटरशैड प्रबंध और अन्य संबंधित उप क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रही है।

(4) क्षेत्रीय असमानताओं में कोई कमी नहीं

बहुत से अध्ययनों से पता चलता है कि नब्बे के दशक में क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, क्योंकि समृद्ध राज्य आर्थिक सुधारों का अधिक लाभ उठाने में कामयाब हुए हैं। और इस प्रकार वे अपनी वृद्धिदरों को महत्वपूर्ण रूपों में बढ़ा सके हैं। अब यह बात स्थापित हो गई है कि समृद्ध राज्यों को अधिकतम लाभ हुआ है परन्तु इनकी तुलना में गरीब और अधिक आबादी वाले राज्यों की वृद्धि दर में अपकर्षण का अनुभव हुआ है।

(5) अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को कम करने में विफलता

(6) क्षेत्रीय ढाँचा अस्त व्यस्त

(7) बच्चों में शिशु मृत्युदर और कुपोषण कम करने में विफलता

निष्कर्ष

दसवीं योजना की उपलब्धियों और विफलताओं की समीक्षा के पश्चात जो तस्वीरें सामने आयी है वह संकेत करती है कि आयोजक इस बात में तो सफल हुए हैं कि वे सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दर को 2006-07 तक 9 प्रतिशत तक के स्तर तक ले गये हैं।

P.T.O

Scanned by CamScanner

और इसके साथ बचत और निवेश को क्रमशः 32 प्रतिशत और 34 प्रतिशत तक बढ़ाने में सफल हुए हैं।

विकास की प्रक्रिया की विडम्बना यह है कि विकास के लाभ निचले स्तर पर रहने वाले गरीब और कमजोर वर्गों तक नहीं पहुँच पाये हैं। परन्तु इनसे समाज के उच्च वर्गों के जेबें ही भरी गई हैं, परिणामतः गरीबी विस्तृत रूपों में फैली हुई है। और योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 2004-05 में 30 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। दैनिक स्थिति आधार (Current daily Status) के अनुसार 2004-05 में बेरोजगारी की दर 8.3 प्रतिशत के ऊपर पहुँच गयी थी। कृषि क्षेत्र में भयंकर विफलता हुई और वास्तविक औसत वार्षिक वृद्धि दर 10वीं योजना के 4 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.1 प्रतिशत रही। क्षेत्रीय असमानताओं में कोई कमी नहीं हुई और 5 गरीब राज्यों में कुल गरीबों की संख्या का 55 प्रतिशत निवास करता है।

जो प्रश्न आलोचक उठाते हैं वह यह है कि :-

विकास किसके लिए? क्या यह आदमी के लिए है या करोड़पतियों एवं अरबपतियों के लिए है। या सामान्यतया समृद्ध वर्गों के लिए। समावेशी विकास को उन्नत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे, इसकी अपेक्षा कि गरीबों और दलितों के लिए मौखिक सहानुभूति ही व्यक्त करते हैं।